खाद सब्सिडी का बोझ तीन लाख करोड़

- यूरिया सब्सिडी में 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- डीएपी पर सब्सिडी 61 प्रतिशत बढ़ी



सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड की कमी बनी चिंता उर्वरक सचिव ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर कच्चे माल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. खासकर सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड की कमी के कारण फॉस्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है. डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों के निर्माण में सल्फर महत्वपूर्ण कच्चा माल है. फरवरी 2026 में वैश्विक बाजार में सल्फर की कीमत 532 डॉलर प्रति टन थी जो बढ़कर 1,050 डॉलर प्रति टन हो गई है. ईरान के खिलाफ युद्ध के बाद कतर में उत्पादन प्रभावित होने से सल्फर की उपलब्धता घटी.

नवभारत न्यूज नेटवर्क.
नयी दिल्ली, 1 अक्टूबर भारत ईंधन के अलावा उर्वरकों का भी बड़ा इंपोर्टर देश है. चीन, रूस सहित कई देशों से किसानों के लिए खाद का आयात किया जाता है. ग्लोबल मार्केट में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार का खाद सब्सिडी बिल चालू वित्त वर्ष में 3 लाख करोड़ के पार जा सकता है.

इस बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से किसानों के बीच उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और जरूरत से ज्यादा खाद के छिड़काव को रोकने की अपील की है. कृषि मंत्रियों के वार्षिक रबी सम्मेलन के दूसरे दिन उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा ने बताया कि युद्ध से पहले और वर्तमान समय की तुलना में सरकार पर प्रति बोरी किलोग्राम की एक बोरी यूरिया पर सब्सिडी का बोझ काफी गया है. 45 सब्सिडी 1,350 रुपये से 2,775 हो गई है, जो 106% की बढ़ोतरी है.

वहीं 50 किलोग्राम की डीएपी की बोरी पर सब्सिडी 2,102 से बढ़कर 3,523 पहुंच गई है, जो 61% अधिक है. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा अनुमान के मुताबिक इस वित्त वर्ष में खाद सब्सिडी का खर्च 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है लेकिन यदि वैश्विक कीमतें और बढ़ती हैं तो यह इससे भी अधिक हो सकता है.

जीएसटी संग्रह सितंबर में 14.7 प्रतिशत बढ़कर 2.03 लाख करोड़ पर

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नयी दिल्ली, 1 अक्टूबर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कुल राजस्व संग्रह सितंबर में 14.7 प्रतिशत बढ़कर 2,03,521 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को सितंबर के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए. इसमें घरेलू जीएसटी संग्रह 10.1 फीसदी बढ़कर 1,37,996 करोड़ रुपये और आयातित माल एवं सेवाओं पर कर से प्राप्त राजस्व 25.9 प्रतिशत बढ़कर 65,525 करोड़ रुपये पर रहा.

घरेलू स्तर पर केंद्रीय जीएसटी सितंबर में 37,762 करोड़ रुपये और राज्यों का जीएसटी 45,363 करोड़ रुपये रहा. वहीं, एकीकृत जीएसटी संग्रह 54,871 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

एयर इंडिया को चाहिए 10 हजार करोड़

- कैशफ्लो पर बैंकों ने उठाए सवाल
- एयरलाइन का कुल घाटा 22,238 करोड़



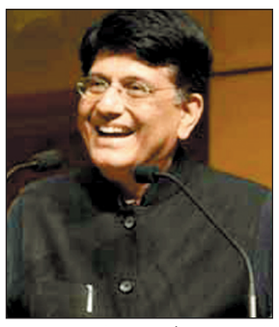
नवभारत न्यूज नेटवर्क
नयी दिल्ली, 1 अक्टूबर एयर इंडिया अपने बेड़े को हानेले और कामकाज के खर्चों के लिए बैंकों से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नया लोन लेना चाहती है. हालांकि कुछ लेंडर घाटे में चल रही एयरलाइन को नया क्रेडिट देने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसके कैशफ्लो के बारे में साफ जानकारी नहीं है.

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बात बताई. यह हिचकिचाहट टाटा ग्रुप की एयरलाइन की एएए क्रेडिट रेटिंग होने के बावजूद है.10,000 करोड़ के नए लोन की जरूरत 22,238 करोड़ रुपये पर पहुंचा कुल घाटा 10,858 करोड़ रुपये था घाटा 1 वर्ष पहलेचल रही है मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा सभी नए एविएशन सेक्टर में मुनाफा कमाने में कुछ समय लगता है और मुनाफे के मामले में कोई असामान्य स्थिति नहीं है. लोन की दरों पर बातचीत चल रही है और एयरलाइन ने पहले ही एक बड़े बैंक से काफी बड़ा लोन हासिल कर लिया है.

एयर इंडिया में हिस्सेदारी का पैटर्न : लैंडर्स के लिए राहत की बातयह भरोसा है कि टाटा संस एयरलाइन में कम से कम 51% हिस्सेदारी बनाए रखेगी. हालांकि लैंडर्स को चिंता है कि लोन का पेमेंट प्रमोटर द्वारा लगातार इक्विटी डालने पर निर्भर हो सकता है. एयर इंडिया में टाटा संस की हिस्सेदारी 74.9% है, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस के पास बाकी 25.1% हिस्सेदारी है. इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने नया लोन देने से पहले एयर इंडिया के कैशफ्लो और सुधार की योजनाओं के बारे में और साफ जानकारी मांगी है. हालांकि सरकारी बैंक मौजूदा क्रेडिट लाइनों को रिन्यू करने के लिए तैयार है, क्योंकि टाटा ग्रुप के साथ उनके संबंध अच्छे है और एयर इंडिया का क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा है, जो सबसे कम जोखिम का संकेत देता है.

गोयल की अमेरिकी-पोलिश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता

- ग्रीर से व्यापार समझौते पर हुई बातचीत
- पोलैंड से व्यापार-निवेश बढ़ाने पर जोर



नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिल्वौकी में आयोजित जी-20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अमेरिका और पोलैंड के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ हुई बातचीत में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई.

वहीं पोलैंड के वित्त मंत्री आंद्रेज डोमांस्की के साथ व्यापार और निवेश संबंध मजबूत करने के नए अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया. गोयल ने अमेरिकी औद्योगिक स्वचालन कंपनी रॉकवेल ऑटोमेशन को भी भारत में अपना कारोबार और निवेश बढ़ाने का न्योता दिया.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है. सरकार के मुताबिक गोयल और ग्रीर की बैठक का उद्देश्य संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना है. फरवरी 2026 में दोनों देशों ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे की घोषणा की थी.

हालांकि, अमेरिका की बदली टैरिफ नीति के बीच समझौते के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत जारी है. गोयल ने रॉकवेल ऑटोमेशन के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की.

उन्होंने कंपनी को भारत के तेजी से बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र, तकनीकी क्षमता और कुशल इंजीनियरिंग प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए भारत में विस्तार करने का आमंत्रण दिया.

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निवेश, विनिर्माण, तकनीक, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों तक बढ़ रहे हैं. पोलैंड के वित्त मंत्री डोमांस्की के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई. गोयल ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार और निवेश के नए अवसर बनने की संभावनाओं पर भी बात की.

एनबीसीसी ने मंत्रालय संग किया समझौता

- 2026-27 के प्रदर्शन लक्ष्य किए तय
- वित्तीय और प्रचालन मानकों पर रहेगा जोर



नवभारत कनेक्ट
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर नवरत्न सीपीएसई, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 30 सितंबर 2026 को अपने प्रशासनिक मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के प्रदर्शन संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है.

इस समझौता ज्ञापन पर मंत्रालय की ओर से डी. तारा (आईएएस), सचिव (सीडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा कंपनी की ओर से डॉ. के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी द्वारा हस्ताक्षर किए गए.

हस्ताक्षर समारोह में रवि कुमार अरोड़ा (आईएएस), संयुक्त सचिव (भूमि एवं संपदा); संजीत (आईआरएएस), संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; संदीप कुलहरिया (आईआरएसएमई), निदेशक (संपदा), एम.ओ.एच.यू.ए.; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य); श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त) एवं एम. बी. सिंघल, कार्यपालक निदेशक (वित्त), एनबीसीसी के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही तथा इस अवसर पर मंत्रालय और एनबीसीसी के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे. समझौता ज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के प्रदर्शन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है तथा वित्तीय एवं प्रचालनात्मक प्रदर्शन संबंधी मानकों के संदर्भ में एनबीसीसी द्वारा हासिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है.

यह सम्मान एनबीसीसी की निरंतर प्रचालन उत्कृष्टता, मजबूत वित्तीय अनुशासन तथा राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में उसके अग्रणी भूमिका को रेखांकित करता है. इस उपलब्धि की गति को बनाए रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में एनबीसीसी ने प्रमुख प्रत्यक्ष मानदंडों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ-साथ मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं.

महीने के पहले दिन सोना-चांदी फिर महंगे

- 24 कैरेट सोना रु. 1.49 लाख के करीब
- चांदी रु. 2.25 लाख प्रति किलो पहुंची

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर. महीने के पहले दिन गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। दो दिन की तेज गिरावट के बाद अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव बढ़े हैं.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना करीब 500 रुपए चढ़कर 1,49,489 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी के भाव में करीब 2,100 रुपए की तेजी आई और यह 2,25,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी. घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना करीब 1,49,170 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,37,700 रुपए और 18 कैरेट सोना करीब 1,12,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा. चांदी करीब 2,26,360 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का रुख रहा। कॉमेक्स पर सोना 0.20% बढ़कर 4,195.10 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.43% चढ़कर 61.45 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, हाल की गिरावट के बाद निचले स्तर पर निवेशकों की खरीदारी से कीमतों को सहारा मिला है.

डीजल-एटीएफ निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटा

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है.

1 अक्टूबर से डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर शुल्क घटा दिया गया है, जबकि पेट्रोल पर लगने वाला शुल्क मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रखा गया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर को 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इसी तरह एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी 15 रुपये से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है. पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.5 रुपये प्रति लीटर ही रहेगा. सरकार ने यह शुल्क कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया के संघर्ष के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाया था.

वाहनों की बिक्री में सितंबर में तेजी रही

नयी दिल्ली, 1 अक्टूबर घरेलू बाजार में गत सितंबर में लगातार 13वें महीने वाहनों की मजबूत बिक्री जारी रही. विशेष रूप से यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और दुपहिया की बिक्री में तेजी देखी गई हालांकि ट्रैक्टरों की बिक्री में गिरावट रही. सरकार के पिछले साल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे में बदलाव के बाद से ही वाहनों की बिक्री मजबूत बनी हुई है.

देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री 1,81,838 इकाई पर रही.

एचडीएफसी बैंक को मिला नया एमडी-सीईओ

अनुप बागची संभालेंगे शशिधर जगदीशन की जगह कमान

नवभारत न्यूज नेटवर्क
मुंबई,1 अक्टूबर एचडीएफसी बैंक ने वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारी अनुप बागची को अपना नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का ऐलान किया है. बागची बैंक के मौजूदा एमडी एवं सीईओ शशिधर जगदीशन की जगह कमान संभालेंगे.

नेतृत्व में बदलाव की इस घोषणा के बाद बैंक की आगे की रणनीति और कारोबार की दिशा पर बाजार की नजर रहेगी.



अनुप बागची वित्तीय सेवा क्षेत्र में लंबे अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारी हैं. वह इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका निभा चुके हैं. बैंकिंग क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए नई जिम्मेदारी के साथ उनसे एचडीएफसी बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है.एचडीएफसी बैंक देश के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल है. बैंक का शीर्ष नेतृत्व बदलने की प्रक्रिया के बीच बागची की नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

नए एमडी एवं सीईओ के सामने बैंक के मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक सेवाओं और प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने जैसी प्राथमिकताएं रहेंगी.

समाचार विशेष

गुरुग्राम में बनेगा इंडिया इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर

भारत की सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 26.69 करोड़ की परियोजना



नवभारत कनेक्ट
नई दिल्ली, 01 अक्टूबर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नवरत्न सीपीएसई, एनबीसीसी लिमिटेड ने गुरुग्राम में प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर के निर्माण के लिए इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी , नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए.

इस एमओयू का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक स्तर पर प्रस्तुतीकरण के लिए समर्पित विश्वस्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करना है. इस एमओयू पर डॉ. योगेंद्र नारायण, आईएएस , अध्यक्ष, इंडिया इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर, गुरुग्राम और डॉ. के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड तथा श्री अंजीव जैन, निदेशक (वित्त), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए. यह परियोजना इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत संचालित की जा रही है. गुरुग्राम में इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थान के विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एमओयू पर डॉ. अमित जैन, अध्यक्ष, इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी एवं श्री राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (इंजी.) एवं एसबीजी प्रमुख, एनबीसीसी ने हस्ताक्षर किए.सेक्टर-9ए, गुरुग्राम में रणनीतिक रूप से स्थित आईआईसीसी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है और द्वारका एक्सप्रेसवे के निकट स्थित है. इस केंद्र की परिकल्पना भारत और विश्व के बीच एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, कलाकारों, विद्वानों और पर्यटकों के लिए सुगम आवागमन प्रदान करेगा. प्रस्तावित केंद्र में एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों और पांडुलिपियों को समर्पित सरस्वती संग्रहालय, एवं भाषाविद्यालय, सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए अत्याधुनिक सभागार तथा विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान केंद्र, पुस्तकालय एवं अभिलेखागार शामिल होंगे.

सपा से रामगोपाल तय, दूसरे पर असमंजस



लखनऊ. उत्तर प्रदेश में खाली हो रही राज्यसभा की 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ एक सीट है. वह सीट अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव की है. इस बार सपा को दो सीटें मिलेंगी. पहली सीट के लिए रामगोपाल यादव का नाम तय है.

वे फिर से राज्यसभा जाएंगे. लेकिन दूसरी सीट पर किसको भेजा जाएगा? यह बड़ा सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार किसी मुस्लिम को राज्यसभा भेजेंगे. अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाएं लेकिन वे दूसरे नंबर पर मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं रखना चाहते हैं. जानकार सूत्रों का कहना है कि दूसरे नंबर पर वे आलोक रंजन को उतारने का मन बना रहे हैं, जिनको पिछली बार लड़ाया था. अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में आलोक रंजन को तीसरा उम्मीदवार बनाया था. जया बच्चन और रामजीलाल सुमन पहले दो उम्मीदवार थे. दोनों जीत गए लेकिन आलोक रंजन हार गए थे. वे उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं.

यह भी कहा जा रहा है कि पुराने नेता सलीम शेरवानी इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं. अखिलेश ने उनको 2024 में टिकट नहीं दिया था तो वे नाराज हो गए थे और इस्तीफा दे दिया था. हालांकि अखिलेश ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया. अब वे फिर पार्टी में सक्रिय हैं और टिकट के दावेदार हैं. लेकिन वे भी तीसरा उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं. तभी अखिलेश यादव की दुविधा बढ़ी हुई है.

सीमांचल-कोसी की सियासत पर भाजपा की नजर

संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने अनंत नारायण मिश्र को मैदान में उतारा



पटना. बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अब सीमांचल और कोसी की सियासत पर संगठनात्मक फोकस बढ़ा दिया है. भागलपुर, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पार्टी ने नवनियुक्त संगठक अनंत नारायण मिश्र को मैदान में उतारा है.

बिहार पहुंचने के बाद वह प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ इन इलाकों का दौरा करेंगे. इस दौरान पार्टी संगठन की जमीनी स्थिति के साथ स्थानीय राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करेगी.

भाजपा के लिए सीमांचल और कोसी क्षेत्र लंबे समय से संगठनात्मक विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहे हैं. पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी अपनी सांगठनिक गतिविधियों को और सक्रिय करने पर जोर दे रही है. वहीं, कोसी क्षेत्र में भी मंडल से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी है. इसी कड़ी में अनंत नारायण मिश्र को इन क्षेत्रों की संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की जिम्मेदारी दी गई है.

सीमांचल व कोसी में भाजपा की चुनौती

बिहार में सत्ता की राजनीति में मजबूत स्थिति के बावजूद सीमांचल और कोसी भाजपा के लिए अलग तरह की राजनीतिक चुनौती हैं. सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज तथा कोसी के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय मुद्दे चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं.

विशेष | छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत मिशन 2028 की तैयारी में जुटे

जनाधार की मजबूती भगत के लिए बड़ी चुनौती

रायपुर. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत दो दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं. अब कांग्रेस अपने नए प्रारूप में नई रणनीति के साथ तैयारी में जुट गई है.

भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार के समक्ष जो चुनौतियां कांग्रेस लेकर खड़ी है उसका जवाब निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आसान नहीं है. क्योंकि जिन आरोपों में कांग्रेस को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी रणनीति बनाती थी, आज इस योजना की तैयारी में कांग्रेस लेकर आई है. छत्तीसगढ़



दौरे पर आ रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत राज्य की राजनीति में उन मुद्दों से निश्चित तौर से रूबरू होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है. साथ ही कांग्रेस की कमजोर कड़ी जो आपसी मतभेद के साथ रही है उसे दूर करने की भी एक बड़ी चुनौती सुखदेव भगत के सामने होगी.

संभव है सुखदेव भगत के समक्ष कांग्रेस पार्टी की अब तक की अपनी बनी हुई रणनीति भाजपा सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत लाइन के तौर पर पड़ी हुई है. अब देखना है कि इस लाइन को और बड़ी करने में सुखदेव भगत किस तरीके से पार्टी को मजबूती देते हैं.

हालांकि कुछ जो पुराने पहलू हैं वह आज भी कांग्रेस के लिए इस चुनौती के तहत खड़े हैं. अगर इसे कांग्रेस जीत लेती है तो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी खड़ा करने में सफल हो जाएगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2028 में होना है और इसके लिए वक्त बहुत है. लेकिन जिन मुद्दों और सियासत को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटी है उसका जवाब निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए पार्टी को संगठित करने का एक बड़ा हथियार इसलिए भी होगा की जमीनी स्तर पर अपने नेताओं से ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है. विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पार्टी के कई मुद्दों पर मुखालफत कर रहे हैं.

महंगाई ने मार दिया, कांग्रेस का बड़ा मुद्दा

बढ़ती महंगाई पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश का थोक महंगाई सूचकांक आजादी के बाद सबसे ऊंचे पायदान 10 (9.78) तक पहुंच गया है. रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों की बेतहाशा बढ़ी महंगाई तथा खाद्य तेल, शक्कर, प्याज के बढ़े दाम आम आदमी को परेशान कर रहे हैं. राशन सामाग्री के दाम दोगुने हो गये है, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस तथा बढ़े बिजली बिल से जनता के घर का बजट बिगड़ गया है.